

पाकस्तान-चीन संबंध और भारत

प्रलम्बिस के लिये:

पंचशील की नीति, हुंजा-गलिगति क्षेत्र, 1999 का कारगलि संघर्ष।

मेन्स के लिये:

भारतीय वदिश नीति, पाकस्तान-चीन संबंध, भारत-चीन संबंधों का इतहास।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वदिश नीतिके बहाने संसद में सरकार से सवाल करते हुए वपिकष ने पाकस्तान और चीन को एक साथ लाने के लिये ज़मिमेदार मौजूदा नीतियों की आलोचना की है।

- इसके जवाब में वदिश मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों देश हमेशा करीबी रहे हैं और कई मोर्चों पर सहयोग का एक समृद्ध इतहास साझा किया है।

पाकस्तान-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि:

- प्रारंभ में पाकस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले दो कमयुनसिट वरिधी सैन्य समझौते 'सीटो और सेंटो' (SEATO and CENTO) का सदस्य था, इसे गैर-सोवियत ब्लाक के हसिसे के रूप में देखा गया था और माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीन वैचारिक स्तर पर इन सबसे अलग था।
 - दूसरी ओर **भारत के चीन के साथ** कामकाजी संबंध थे। दोनों देशों का उपनविश-वरिधी, गुट-नरिपेक्ष दृष्टिकोण समान था और इन्होंने मलिकर पंचशील की नीति दी।
 - हालाँकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के कारण यह संबंध जल्दी बदल गया।
- 1962 का युद्ध: 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण चीन ने पाकस्तान के साथ घनषिट संबंध वकिसति किये।**
 - वर्ष 1963 में एक सीमा समझौते में पाकस्तान ने शकसगाम घाटी को चीन को सौंप दिया।
 - शकसगाम घाटी या **ट्रांस काराकोरम ट्रेक्ट** पाकस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हुंजा-गलिगति क्षेत्र का हसिसा है और यह भारत द्वारा दावा किया गया क्षेत्र है लेकिन पाकस्तान द्वारा नयितरति है।
 - इस समझौते के माध्यम से 1970 के दशक में चीन और पाकस्तान द्वारा संयुक्त रूप से नरिमति काराकोरम राजमार्ग की नींव रखी गई।
- 1965 का युद्ध: 1965 के भारत-पाकस्तान युद्ध में पाकस्तान को चीन से कूटनीतिक समर्थन मिला।**
 - वशिलेषकों का कहना है कि 1962 में चीन के खलिाफ युद्ध में भारत की हार के बाद पाकस्तान को आकरामकता के लिये उकसाया गया था।
- अमेरिका-चीन और पाकस्तान:** इनका वास्तविक राजनयिक मलिन 1970 के दशक में शुरू हुआ जब पाकस्तान ने रचिर्ड नकिंसन और हेनरी कसिजिर तथा चीन के माओ एवं झोउ एनलाई के नेतृत्व वाले देशों के बीच पहुँच स्थापति की।
- परमाणु सहयोग:** चीन एवं पाकस्तान के बीच संबंध 1970 और 80 के दशक में वकिसति हुए। खासकर वर्ष 1974 में भारत द्वारा परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के बाद परमाणु सहयोग प्रमुख स्तंभों में से एक था।
 - चीन ने पाकस्तान को परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी वकिसति करने में मदद कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - सितंबर 1986 में दोनों देशों द्वारा असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
 - चीन वर्ष 1991 में पाकस्तान को अपने स्वदेशी रूप से वकिसति Qinshan-1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Qinshan-1 Nuclear Power Plant) की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ।
 - वर्ष 1998 में भारत द्वारा अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण** करने के बाद पाकस्तान ने चीन की मदद से इसका अनुसरण किया।

भारत-चीन संबंधों का इतहास:

- वर्ष 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के साथ भारत और चीन के बीच तालमेल की एक महत्त्वपूर्ण प्रकरिया शुरू हुई।
- चीन द्वारा एक स्पष्ट बदलाव के संकेत देखने को मल्लि जहाँ उसने भारत के साथ संबंधों को आर्थिक हतियों के साथ जोड़ा और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं दूसरी ओर उसने सीमा विवाद पर भारत से अलग से बात की।

- इसके बाद से चीन ने भारत और पाकस्तान को लेकर सतर्क रुख अपनाया ।
- वर्ष **1999 के कारगिल युद्ध** के दौरान चीन ने पाकस्तान को सलाह दी कि वह सैनिकों को वापस बुला ले तथा आत्म-नयित्तरण बरते ।
- वर्ष 2002 में संसद पर हमले, ऑपरेशन पराक्रम बलिडअप और वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद भी चीन द्वारा इसी प्रकार का रुख अपनाया गया ।
- फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले के दौरान भी चीन द्वारा इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

भारत-चीन-पाकस्तान ट्राइएंगल की वर्तमान स्थिति:

- वर्ष 2005-06 में परमाणु समझौते से शुरू हुई अमेरिका-भारत नकटता ने चीन और पाकस्तान दोनों को चिन्तित कर दिया ।
- चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना**, **चीन-पाकस्तान आर्थिक गलियारे** (CPEC) से संबंधित है जो भारत द्वारा दावा किये गए विवादित क्षेत्र से होकर गुजरती है ।
 - चीन के दृष्टिकोण से यह बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी हिंद महासागर तक पहुँच प्रदान करती है ।
 - हालाँकि भारत के दृष्टिकोण से ग्वादर बंदरगाह भारत को घेरने के लिये चीन की स्ट्रैटिज ऑफ परल्स रणनीति का एक हिस्सा है ।
- अगस्त 2019 में भारत द्वारा **अनुच्छेद 370** को नरिस्त करने तथा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के नरिणय ने चीन व पाकस्तान को और भी करीब ला दिया है ।
- वर्ष 2020 में चीन द्वारा पाकस्तानी सेना और पीपुल्स लबरेशन आरमी के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु पाकस्तान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं ।
 - पाकस्तान ने चीन में नरिमति लड़ाकू ड्रोन या मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान खरीदे हैं ।
- पाकस्तान **दक्षिण चीन सागर**, **ताइवान**, **शनिजियांग** और **तबिबत** सहित मुख्य मुद्दों पर चीन का समर्थन करता है ।
- तालबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद चीन को पाकस्तान की मदद से और संसाधनों हेतु अफगानिस्तान में प्रवेश करने का मौका मिला गया है ।

भारत के लिये चीन-पाकस्तान नकटता के नहितार्थ:

- **दो मोर्चे पर युद्ध:** दोनों देशों के बीच नकटता एक 'दो-मोर्चे पर युद्ध' के विचार को जन्म देती है ।
- **अधगिरिहीत क्षेत्रों पर बातचीत:** चीन अब अकसाई चिन, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एवं सकिक्मि जैसे भारतीय क्षेत्रों को 'पुनर्प्राप्त' करने के लिये बातचीत करना चाहता है ।
 - यह वार्ता कश्मीर तथा संबंधित क्षेत्रों में चीन की भूमिका को बल प्रदान करेगी ।
- **वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय:** चीन और पाकस्तान दोनों का साझा उद्देश्य वैश्व शक्ति के रूप में भारत के उदय को रोकना है ।
 - वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय के साथ पाकस्तान और चीन की वर्तमान साझेदारी को भारत पहले की तुलना में अधिक चिन्ता का विषय मानता है ।

आगे की राह

- **दक्षिण एशियाई संबंधों में सुधार:** सबसे पहले भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करने के लिये उचित कदम उठाने होंगे ।
 - चीन और पाकस्तान इस क्षेत्र में भारत को नयित्तरति और प्रतबिधति करने का प्रयास कर सकते हैं ।
- **पड़ोस के साथ संबंधों में सुधार:** ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री सहयोग बढ़ाने एवं वसितारति करने हेतु इसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मज़बूत करने की आवश्यकता है ।
- **रूस के साथ संबंधों में सुधार:** भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करना चाहिये, क्योंकि रूस भारत के खिलाफ क्षेत्रीय गंभीरता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।
- **कश्मीर की स्थिति में सुधार:** दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कश्मीर में राजनीतिक पहुँच का उद्देश्य पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान कर वहाँ शांति स्थापित करना है ।
- **भारत-प्रशांत रणनीति में सुधार:** भारत के लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय भागीदारों को शामिल करने वाली **भारत-प्रशांत रणनीति** एक महत्त्वपूर्ण बाधा है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस